भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3889
9 अगस्त, 2016 को उत्तरार्थ

विषय: बीटी कपास की खेती

3889. श्रीमती रंजीत रंजनः
श्रीमती वीणा देवीः
डॉ. बूरा नरसैय्या गौडः
श्री राजेश रंजनः
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजराः
श्री डी.एस. राठौड़ः
श्री कल्याण बनर्जीः
श्री जैदेव गल्लाः
श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोशः
श्री दुष्यंत चौटालाः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बीटी कपास की खेती देश में परंपरागत कपास किस्मों की तुलना में अधिक लाभदायक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार प्रति एकड़ बीटी कपास उत्पादन में कितनी वृद्धि/गिरावट हुई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में कपास का उत्पादन लक्ष्यों की तुलना में काफी कम रहा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार इसके क्या कारण हैं;

(घ) संयुक्त राज्य अमरीका और चीन की तुलना में देश में प्रति एकड़ कपास उत्पादन का ब्यौरा क्या है तथा इसमें वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार ने कपास की कीमत में गिरावट को रोकने और कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के प्रयोजनार्थ कपास के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परामर्श से क्या कदम उठाए हैं/प्रस्तावित किए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया)

(क) और (ख): जी हां। परंपरागत कपास किस्मों में बीटी जीन नहीं पाये जाते हैं जो लेपीडॉपटेरन कीटों विशेषकर बॉलवार्म के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। बीटी कपास में ऐसे "बीटी जेनों" पाये जाते हैं जो बॉलवार्म फसलों को सुरक्षा प्रदान करता है। बॉलवार्म के अधिक संक्रमण की स्थितियों में बीटी कपास की खेती लाभदायक होती है। अन्य अवधि के दौरान जब बॉलवार्म का संक्रमण कम होता है, बीटी कपास की खेती के प्रारंभ से कई वर्षों के दौरान कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें अच्छे सस्य विज्ञान प्रबंधन के साथ परांगत कपास किस्मों की खेती बीटी कपास जितनी ही लाभदायक हो सकती है।

वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान बीटी कपास के तहत राज्य-वार क्षेत्र **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ग): कपास का उत्पादन वर्ष 2014-15 में 348.05 लाख टन से 2015-16 (4वां अग्रिम अनुमान) में 301.47 लाख टन रह गया है जिसका मुख्य कारण प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों यथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश आदि में सूखे जैसी स्थिति, पंजाब एवं हरियाणा में व्हाइटफ्लाई समस्या और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पिंक बॉलवार्म समस्या है। वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान कपास का राज्य-वार लक्ष्य एवं उत्पादन अनुबंध-II पर दिया गया है।

(घ): संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के साथ-साथ देश में प्रति हैक्टेयर कपास पैदावार निम्नलिखित है:

फाहा उपज (कि.ग्रा./हैक्ट.)

देश	2013-14	2014-15
सं.रा.अ.*	920.60	939.30
चीन*	1478.70	1508.10
भारत**	510	462

*स्रोत:- अंतरराष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति
** स्रोत:- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष2014-15 से 15 प्रमुख कपास उत्पादक राज्य यथा असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत फसलन प्रणाली दृष्टिकोण पर फोकस के साथ कपास विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना के तहत समेकित फसल प्रबंधन (आईसीएम), देशी एवं अत्यधिक लम्बे रेशे का कपास, उच्च घनत्व रोपण प्रणाली पर फ्रंट लाइन प्रदर्शन (एफएलडी) के माध्यम से कपास उत्पादकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु बल दिया जाता है। राज्य कृषि विभाग (एसडीए), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) आदि के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इसके अलावा राज्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत कपास विकास कार्यक्रम को सहायता प्रदान कर सकता है।

(ङ.): वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत एक नई योजना नामत: ''भारत से व्यापार निर्यात (एमईआईएस)'' शुरू की है जिसमें विशिष्ट मंडियों के लिए विशिष्ट सामानों/उत्पादों के निर्यात हेतु निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में एमईआईएस के तहत कपास (आईटीसी कोड: 57049010) के लिए निर्यात प्रोत्साहन सभी देश क, ख, और ग समूह के लिए 5 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने कृषि उत्पादों के निर्यात में तेजी लाने के लिए विभिन्न योजनाओं यथा मंडी विकास सहायता (एमडीए), मंडी सहायता पहल (एमएआई), विकसित निर्यात अवसंरचना एवं सम्बंधित कार्यकलापों के लिए राज्य को सहायता (एएसआईडीई) आदि की शुरूआत की है।

भारतीय कपास निगम (सीसीआई) घरेलू मूल्य स्थिति की गहन निगरानी कर रहा है। न्यूनतम सर्मथन मूल्य (एमएसपी) का लाभ देने के लिए और कपास किसानों की बड़ी संख्या को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने सभी उत्पादक राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रचालन करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को उस समय नामित करती है जब कपास बीज के मूल्य एमएसपी दर पर विभिन्न कृषि उत्पाद मंडी समिति (एपीएमसी) मंडी परिसर में कपास किसानों द्वारा दिए गए कपास (एफएक्यू ग्रेड) की समग्र मात्रा खरीद करने के लिए एमएसपी स्तर तक पहुंच जाती है।

वर्तमान में कपास का निर्यात ओपन जनरल लाईसेंस के तहत है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 102(आरई-2013)/2009-14 दिनांकित 08.12.2014 से कपास का आयात और निर्यात के लिए सुविधा प्रदाता होने के कारण कपास के निर्यात के लिए आवश्यक पंजीकरण को अलग कर दिया है।

इसके पश्चात् निर्यात कार्यकलापित अर्थात 1 प्रतिशत की कमी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 110/2015 - उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांकित 16.11.2015 के माध्यम से टेरिफ मद 5201 के तहत आने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए उपलब्ध है।

अनुबंध-I

अ.ता.प्र.सं. 3889

पिछले 3 वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार बीटी कपास क्षेत्र

(लाख हैक्ट. क्षेत्र में)

राज्य	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
आंध्र प्रदेश	23.65	7.88	6.50	2.82
तेलंगाना		16.01	16.61	11.10
मध्य प्रदेश	4.40	5.20	4.86	4.73
गुजरात	21.25	27.13	26.23	16.30
महाराष्ट्र	37.72	40.10	34.40	30.82
कर्नाटक	5.63	6.97	4.87	2.15
तमिलनाडु	1.30	1.58	0.90	0.02
पंजाब	4.24	4.08	3.05	2.43
हरियाणा	4.67	6.31	5.27	3.64
राजस्थान	2.50	3.95	3.56	2.43
कुल बीटी क्षेत्र	105.36	119.21	106.25	76.44
अखिल भारत कुल कपास क्षेत्र	119.60	128.19	118.72	92.33
कुल बीटी क्षेत्र का प्रतिशत	88.09	92.99	89.49	82.79

*28.07.2016 तक कपास सीजन 2016-17 के दौरान बुआई क्षेत्र

स्रोत: कपास विकास निदेशालय, नागपुर

अनुबंध-II

अ.ता.प्र.सं. 3889

2012-13 से 2015-16 के दौरान प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के राज्य-वार लक्ष्य एवं उत्पादन

(उत्पादन प्रत्येक 170 किग्रा. भार वाली लाख गांठ में)

राज्य	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16*	
	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन
आंध्र प्रदेश	50.00	73.50	61.00	69.56	61.00	28.41	62.00	24.00
तेलंगाना						38.00		38.60
गुजरात	120.00	88.50	108.00	101.50	108.00	105.00	108.00	97.00
हरियाणा	26.50	25.00	23.00	23.02	23.00	23.00	23.00	13.50
कर्नाटक	12.00	12.55	11.00	18.75	11.00	23.11	11.50	16.00
मध्य प्रदेश	20.00	22.00	17.00	17.30	17.00	17.50	17.00	20.98
महाराष्ट्र	73.00	76.55	87.00	88.34	87.00	70.00	87.00	65.00
ओडिशा	3.50	4.00	4.00	2.99	4.00	4.00	4.00	4.00
पंजाब	23.00	20.00	22.00	19.68	22.00	16.00	22.00	4.50
राजस्थान	13.35	14.00	13.00	12.87	13.00	15.27	13.00	13.20
तमिलनाडु	5.00	5.00	3.00	4.08	3.00	6.86	3.00	3.69
अन्य	3.65	1.10	1.00	0.93	1.00	0.90	1.00	1.00
अखिल भारत	350.00	342.20	350.00	359.02	350.00	348.05	351.50	301.47

*4वां अग्रिम अनुमान

****